MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :—

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 11th March, 1969, adopted the following motion in regard to the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Contempt of Courts Bill, 1968 :—

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Bill to define and limit the powers of certain courts in punishing contempts of courts and to regulate their procedure in relation thereto be extended up to the last day of the Sixty-ninth Session of the Rajya Sabha."

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Forty-fifth Report

SHRI R. K. KHADILKAR (Khed) : I beg to present the Forty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

Twenty-sixth Report

SHRI G. S. DHILLON (Taran Taran) : I beg to present the Twenty-sixth Report of the Committee on Public Undertakings on Trombay Unit of Fertiliser Corporation of India Ltd—Paras in Section II of Audit Report (Commercial), 1968.

CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL

Report of Joint Commitee, Evidence and Memoranda

SHRI SHANTILAL SHAH (Bombay-North-West) : I beg to present the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Constitution of India.

Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Evidence given before the Joint Committee on the Bill further to amend the Constitution of India.

I lay on the Table copies of Memoranda/Representations/Telegrams received by the Joint Committee on the Bill further to amend the Constitution of India.

12.30 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

Madhya Pradesh Governor's Action With Regard to Formation of Ministry

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत, आपकी इजाजत से मैं सदन में मध्य प्रदेश का मामला उठाना चाहता हूँ। पश्चिमी बंगाल के बाद अब मध्य प्रदेश में एक संवैधानिक नाटक खेला जा रहा है। प्रश्न बुनियादी है और वह प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार का भाग्य का निर्णय क्या राज्यपाल महोदय करेंगे या मध्य प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे ? वहां की सरकार की तकदीर का फैसला राज भवन में होगा या विधान सभा भवन में होगा ? मध्य प्रदेश की विधान सभा इस समय चल रही है। विधान सभा बुलाई जाये या न बुलाई जाये, यह सवाल किसी के सामने नहीं है। उस विधान सभा में संयुक्त विधायक दल का बहुमत है और प्रचंड बहुमत है। विधान सभा की बैठक हो रही है लेकिन उसमें प्रतिपक्ष को—मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रतिपक्ष में है अपनी शक्ति का परीक्षण करने का साहस नहीं हुआ। संयुक्त विधायक दल ने अपना नया नेता चुना। नये नेता के चुनाव के निर्णय को लेकर मध्य प्रदेश विधान सभा के संयुक्त विधायक दल के नेता राज्यपाल से मिलने के लिए गए लेकिन राज्यपाल महोदय सो चुके थे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भी परिवर्तन होते हैं, विभाग बदले जाते हैं तो राष्ट्रपति को सोते हुए से उठाया जाता है, उनको